सरगना पर नकेल

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबंध समिति आज जब एक बार फिर आतंकी गिरोह जैशे-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, तो सबकी नजर चीन के रवैये पर होगी. बीते 10 सालों में चौथी बार यह मुद्दा समिति के सामने है. भारत ने अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की से समर्थन के लिए बात की है. इन देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं. भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर सक्रिय उन गिरोहों पर ठोस कार्रवाई करे, जो भारत में आतंकी हमलों के षड्यंत्रकारी हैं तथा भारत में हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिए लिए प्रयासरत हैं. संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को लगातार समर्थन मिलता रहा है, लेकिन मसूद अजहर के मामले में चीन के रुख से उस पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकी है. सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य के रूप में मिले विशेषाधिकार से वह सरगना को बचा लेता है. यह एक विडंबना ही है, क्योंकि जैशे-मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र की उस सूची में शामिल है, जिसमें पाकिस्तान के 139 आतंकी समूहों का नाम है. यह सवाल चीन और पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि जब गिरोह को आतंकी सूची में शामिल किया जा सकता है, तो उसके सरगना को क्यों नहीं. चीन ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद् के नियमों और अपने रुख का हवाला देते हुए मसूद अजहर के विरुद्ध सबूतों की मांग की है. उसने इस मुद्दे पर बातचीत की जरूरत भी बतायी है. इससे जाहिर है कि उसकी मंशा फिर प्रस्ताव को रोकने की है. पाकिस्तान में भारी निवेश करनेवाले चीन को इन गिरोहों के बारे में जानकारी न हो, यह बात गले नहीं उतरती है. दरअसल, दक्षिण एशिया में चीन अपने सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता है. यह उसके निवेश की सुरक्षा की गारंटी भी है, जिसके लिए उसे पाकिस्तानी सरकार और सेना के साथ चरमपंथी और आतंकी समूहों का साथ भी चाहिए. चीन उन मंचों पर पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता रहा है, जहां उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे- इस्लामिक सहयोग संगठन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन. चीन को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से भारत के संबंधों की बेहतरी रास नहीं आ रही है. वह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और सुरक्षा परिषद् में सदस्यता के भारतीय दावे विरोध करता रहा है. साउथ चाइना सी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और बेल्ट-रोड परियोजना में चीन के आक्रामक विस्तार की नीति का भारत आलोचक रहा है. इन मसलों पर कूटनीति का रास्ता अपनाने के बजाय चीन आतंकियों का परोक्ष साथ देकर दक्षिण एशिया में अशांति और अस्थिरता को ही बढ़ावा दे रहा है. बहरहाल, भारत को आतंक के मुद्दे पर व्यापक समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि देर-सबेर चीन और पाकिस्तान भी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे.

पाकिस्तान में भारी निवेश करनेवाले चीन को इन गिरोहों के बारे में जानकारी न हो, यह बात गले नहीं उतरती है.

भारत के लिए घोषणापत्र

प्रभु चावला
वरिष्ठ पत्रकार
prabhuchawla
@newindianexpress.com

राजनीतिक महाभारत का नवीनतम संस्करण व्यूह-रचना के दौर में है. आधा दर्जन राष्ट्रीय तथा पचास से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां अपने घोषणापत्र रूपी मिसाइलों के साथ रणक्षेत्र में जाने को तैयार हैं, जिनमें नया भारत, समावेशी भारत, सहिष्णु भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत एवं एकजुट भारत जैसे नारों की बारूद भरी हुई है. पर क्या जनादेश हेतु प्रस्तुत ये सभी घोषणापत्र अपने शब्दों पर खरे उतरेंगे अथवा उनके सभी सजावटी शब्द गंदे, गाली-गलौज भरे, अपमानजनक, जातिवादी तथा मूर्खतापूर्ण मौखिक हमलों में बदल जायेंगे? पिछले कुछ चुनाव सकारात्मक वादों से कहीं ज्यादा नकारात्मक बयानियों के बूते जीते गये हैं. पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के सारगर्भित शब्दों में कहें, तो 'केवल घोषणापत्र के मुखपृष्ठ पर एक नया चित्र चस्पा हो जाता है, जबकि बाकी चीजें लगभग वही रहती हैं, क्योंकि उनमें से कभी कोई भी पूरी नहीं की जाती.'

ग्रामीण भारत के इस यथार्थवादी नेता के इस कथन में दम है, जिनके दशकों बाद आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी तथा सबसे तेज बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है. पिछले तीन दशकों के दौरान राष्ट्र की प्रतिव्यक्ति आय में 300 फीसदी का इजाफा हुआ है. भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत आज पहले से कहीं ज्यादा वजनी है. यहां विश्वस्तरीय विमानपत्तन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं. घरेलू नागर विमानन उद्योग दो अंकों की दर से वृद्धि पा रहा है. पिछले एक दशक में देश के अरबपतियों की तादाद में 500 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी है. विश्व के 200 शीर्ष धनाढ्यों में दर्जन से ज्यादा भारतीय हैं. मगर गरीबी हटाओ आज भी एक प्रासंगिक सियासी नारा है.

हमारे सामाजिक तथा सियासी परिदृश्य को एक विडंबना परिभाषित किया करती है. पहले भारत को एक ऐसा समृद्ध देश माना जाता था, जहां निर्धन आबादी निवास करती है, मगर आज यह एक ऐसा समृद्ध राष्ट्र है, जो चंद महाधनिकों के हाथों बंधक बना पड़ा है. यहां यत्र-तत्र विपुलता अवश्य बिखरी है, पर गरीबी रेखा से नीचे निवास करनेवाली सबसे बड़ी जनसंख्या भी यहीं मौजूद है. आजादी के 71 वर्षों बाद भी हमारे सियासतदां कृषि ऋण माफ करने की बातें किया करते हैं. चार दशक पूर्व कृषि जीडीपी में 50 प्रतिशत का योगदान करते हुए 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए आय का स्रोत थी. आज उसका यह योगदान घटकर 17 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जबकि उस पर 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी निर्भर है. प्रत्येक चुनावी घोषणापत्र ने उनके साथ बेहतर व्यवहार के वादे कर उन्हें ठगा है, किंतु किसानों की आत्महत्याएं अंतहीन ढंग से बढ़ती ही जा रही हैं.

इस देश की मुश्किलों का ज्यादातर दारोमदार आरक्षण की विकृति का है. दस वर्षों के लिए जाति आधारित आरक्षण सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का साधन बना था, मगर आज ज्यादा से ज्यादा जातियां आरक्षण की आस लगाये बैठी हैं. सियासी पार्टियां गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के ढोल पीटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देतीं, फिर भी सात दशक बाद प्रत्येक चौथा भारतीय गरीबी रेखा से नीचे ही है. हर अगले घोषणापत्र में ये नेता करोड़ों रोजगारों के वादे बांटते हैं. पर प्रत्येक दस योग्य युवाओं में एक लाभप्रद रोजगार से वंचित है. प्रत्येक पांच वर्ष पर नेतागण गरीबों के लिए सस्ते आवासों की सौगंध खाते हैं, पर प्रत्येक पांचवां परिवार अपने सिरों पर बगैर किसी पक्के छत के दिन-रैन गुजारता है. मतों की भिक्षा मांगनेवाले सबके लिए पेयजल की रोजाना आपूर्ति के आश्वासन दिया करते हैं, किंतु 70 प्रतिशत से भी अधिक भारतीयों को दैनंदिन आधार पर स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं होता. विश्व की 16 फीसद आबादी को मीठा जल मुहैया कराने का जिम्मा कांधे पर लिए इस देश के हिस्से में विश्व के मीठे जल भंडार का कुल चार फीसद ही मौजूद है.

विभिन्न दलों के घोषणापत्रों में वनों में वृक्षों की बातें निश्चित रूप से नहीं होंगी. सियासी पार्टियों को चाहिए कि वे भाषणबाजी की स्पर्धा छोड़ प्रयोजनपरक देशभक्ति का वरण करें.

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अद्भुत शब्दावलियां हैं. हमारे अतीत के किसी अन्य नेता ने भारतीय मानस में बुनियादी बदलाव लाने को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व नहीं प्रदान किया. मगर शुरुआती सफलताओं के बाद नामचीन बदलाव दूतों ने उनके सपने के समर्थन में अपनी दिलचस्पी खो दी. हमारे अधिकतर नगर कचरे से भरे हैं, जबकि छोटे कस्बे और गांव और भी बदतर हालत में हैं. बदतरीन होते शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के द्वारा विश्वस्तरीय स्वच्छता एवं सुचारुता के प्रतीक बना मोदी ने उन्हें निवेशकों तथा सैलानियों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने का लक्ष्य तय किया था. पर अधिकतर प्रशासकों ने इस योजना का मजाक बनाकर रख दिया. स्कूलों, ग्रामीण परिवारों एवं शहरी मलिन बस्तियों में शौचालय निर्माण की बड़ी परियोजनाएं 'मैला भारत' के ठप्पे से मुक्ति हेतु चलायी गयी थीं. किंतु नागरिक योजना निर्माताओं ने उसके साथ ही सतत जलापूर्ति तथा देखभाल कर्मियों की व्यवस्था नहीं की. नतीजतन कम से कम 16 प्रतिशत नव निर्मित शौचालय अनुपयोगी बने पड़े हैं.

हमारे नेता आइआइटी, आइआइएम तथा एम्स जैसे शिक्षा के प्रत्येक उत्कृष्ट संस्थान पर प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये खर्च कर गर्व किया करते हैं, जिसमें दो हजार से भी कम छात्रों को प्रवेश मिलता है. पर 70 वर्षों बाद भी हमारे अधिकतर स्कूलों को प्रशिक्षित शिक्षक एवं बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हो सकी हैं. निजी स्वास्थ्य चर्या संस्थान एवं इंश्योरेंस कंपनियां चांदी पीट रही हैं, जबकि ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों की 80 प्रतिशत आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जहां से गंभीर रोगग्रस्त मरीज बड़े शहरों की ओर भागते हैं.

इन घोषणापत्रों में वनों में वृक्षों की बातें निश्चित रूप से नहीं होंगी. सियासी पार्टियों को चाहिए कि वे भाषणबाजी की स्पर्धा छोड़ प्रयोजनपरक देशभक्ति का वरण करें. नब्बे के शुरुआती दशक के सुधारों का उद्देश्य संपदा का निर्माण था और उन्हें उसमें सफलता भी मिली. मगर हुआ यह कि उसका 90 प्रतिशत अंश भारत के चार प्रतिशत लोगों के पास चला गया. सभी देशवासियों को समृद्ध-स्वस्थ बनाने हेतु आवश्यक यह है कि ये घोषणापत्र भारत के लिए न कि इंडिया के लिए बनाये जायें. याद रखें कि प्रत्येक दूसरा भारतीय गांवों-कस्बों में रहता है. स्वस्थ, समृद्ध, स्वच्छ तथा समावेशी भारत के निर्माण हेतु हमारा मंत्र स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छ चिकित्सा, स्वच्छ शासन तथा स्वच्छ सोच होना ही चाहिए. गरीबी के सागर में समृद्धि तथा विलासिता के चंद द्वीपों के दृश्य का मेरा भारत महान की सोच के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता.

(अनुवाद: विजय नंदन)

अमेरिका समझे भारत का पक्ष

शशांक
पूर्व विदेश सचिव
delhi@prabhatkhabar.in

हमारे विदेश सचिव विजय गोखले अमेरिका गये हुए हैं और वहां के विदेश मंत्री माइक पांपियो से बातचीत हुई है. यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. मुझे लगता है अमेरिका ने अपना स्तर बढ़ाकर हमारे विदेश सचिव से बात की है. दोनों देशों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकवादियों को जड़ से खत्म करे. यह केवल पाकिस्तान को सलाह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को सावधान हो जाने का संदेश भी है कि वह भारत-अमेरिका के संदेश व वर्तमान स्थितियों को सरलता से न ले. यह बहुत बड़ी बात है.

दूसरी बात यह है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट व अन्य जगहों पर एयर स्ट्राइक कर चुका है, भले पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद गवाहों के बयान और भारत अपना पक्ष स्पष्ट कहता है कि एयर स्ट्राइक हुई है और खासी सफल स्ट्राइक हुई है, जिससे पाकिस्तान और उसके अंदर के जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं को चेतावनी गयी है कि भारत उन्हें छोड़नेवाला नहीं है. अब अमेरिका के साथ निकले संयुक्त बयान ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि उसका समय आ गया है कि आज तक उसने जिन आतंकी तत्वों को पैदा किया है, पनाह दी है, फंडिंग दी है, उन्हें खत्म करने का समय आ गया है.

चीन की तरफ से भी अब उम्मीद बंध गयी है कि सुरक्षा परिषद् में जब जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद मजहर का मसला उठाया जायेगा, तब चीन अपना रवैया बदलकर रखेगा. चीन खुद भी आतंकवादियों से पीड़ित है और उसने कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकियों को जेल में डाल रखा है. जेल में पड़े ऐसे तत्वों की संख्या करीब 10 लाख है. पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग चलाते हैं, मिल-जुल कर रहते हैं. चीन ने पाकिस्तान को कह दिया है कि यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा. इसलिए, इस बार सुरक्षा परिषद् में जब भारत की मदद के लिए मसला उठाया जायेगा, तो वह रोड़ा नहीं अटकायेगा. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है.

अमेरिका दक्षिण एशियाई इलाकों से आतंकवाद को खत्म करवाना चाहता है, क्योंकि वह पहली प्राथमिकता के तौर पर अब अपनी फौज को अफगानिस्तान व मिडिल ईस्ट से वापस बुलाना चाहता है. लेकिन, वह ऐसी स्थिति में नहीं इलाका छोड़ना चाहता कि आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पर पूरा-का-पूरा नियंत्रण स्थापित कर लें. अमेरिका इसीलिए चिंतित है. अतीत में पाकिस्तान जिस तरह का रवैया अपनाता रहा है और चीन उसकी मदद करता रहा है, उसी को देखते हुए ही भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देने की जरूरत महसूस की है.

जहां तक व्यापार की बात है, भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का स्तर वह नहीं है, जो अमेरिका और चीन के बीच मतभेद का है. अमेरिका चाहता है कि भारत ई-रिटेल और क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर भारतीय लोगों के डेटा को भारत के भीतर ही रखने की शर्त न लगाये और टैक्स भी न लगाये. इस तरह की चेतावनी अमेरिका ने भारत को दी है. भारत का कहना है कि पिछले तीन सालों में अमेरिका के बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो भारत के फेवर में था उसमें कमी आयी है. इस संदर्भ में भी विदेश सचिव ने बातचीत की है. अमेरिका ने इतने देशों को जीएसपी सुविधा दे रखी है, पाकिस्तान को तो जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज) प्लस सुविधा दे रखी है, जबकि पाकिस्तान दोहरा नीति वाला देश रहा है. एक तरफ अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के ऊपर बात करना चाहता है, दूसरी तरफ भारत पर ऐसी कार्रवाई कर रहा है, और टैरिफ लगाना चाहता है. भारत की जिस ड्यूटी से वह खफा बताता है, वह हैंडीक्राफ्ट से जुड़े गरीब लोगों को राहत देने के लिए रहा है, मिडिल क्लास की राहत के लिए रहा है. दूसरी तरफ, अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत में ड्यूटी टैक्स का बड़ा कारण देश में औद्योगीकरण की स्थिति का कमजोर होना है, जिसे मजबूत करने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.

तकनीकी स्तर पर बात करें, तो विदेश सचिव विजय गोखले उच्चतम स्तर के अधिकारी हैं. इससे ऊपर केवल राजनीतिक स्तर के लोगों का ही पद होता है. जितने भी तरह के मसले हैं, चाहे रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार का मसला हो, विदेश सचिव अमेरिका को समझा पाने में सफल रहेंगे. भारत का रवैया बहुत बदला है. रूस से हथियार की खरीद भी हमने लगभग आधी कर ली है, ऐसे कई मसले हैं. एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है. चुनाव भी नजदीक है. भारत को जिन संसाधनों की जरूरत लगती है, वह खरीद रहा है. यह सब अमेरिका को समझना होगा. जैसे, ईरान से तेल खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वह हमारा दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है. फिर भी हमने उसके साथ व्यापार बहुत कम कर लिया है. जबकि, अफगानिस्तान को स्थिर करने के लिए भारत ने अफगान-ईरान के साथ समझौता किया है. और यह अमेरिका की प्राथमिकता भी रही है. इसलिए, उसे भारत का पक्ष भी समझना चाहिए.

(बातचीत : देवेश)

अतीत में पाकिस्तान जिस तरह का रवैया अपनाता रहा है और चीन उसकी मदद करता रहा है, उसी को देखते हुए ही भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देने की जरूरत महसूस की है.

बोधि वृक्ष

एकाग्रता

आध्यात्मिक साधना का अभ्यास स्थूल मन को, मानव मन में और मानव मन को देव मन में रूपांतरित करने का प्रयास है, इसलिए आध्यात्मिक साधकों को इन समस्याओं का समाधान करना है, उन्हें नयी समस्याएं पैदा नहीं करनी है. आध्यात्मिक साधना सभी के लिए है. और प्रथम चरण में एकाग्रता की प्रक्रिया भौतिक-मानसिक है और द्वितीय चरण में इसकी प्रक्रिया मानसिक-आध्यात्मिक होती है. एक मनुष्य को एक भौतिक देह है, एक मन है और एक आत्मा है. अतः प्रथम चरण में आध्यात्मिक अभ्यास भौतिक-मानसिक होना चाहिए. भौतिक स्तर से इसका आरंभ और इसका शीर्ष बिंदु, भौतिकता और मानसिकता का मिलन बिंदु है. भौतिक-मानसिक स्तर पर यही प्रक्रिया है. और इसके अगले चरण में यह मानसिक-आध्यात्मिक होगा. इसका आरंभ मानसिक स्तर से और अंत होगा आध्यात्मिक स्तर पर. मानव मन बहुत सारी वृत्तियों से परिचालित होता है. मानव मन में बहुत सी वृत्तियां हैं. मन में जटिलता होने के कारण उसकी भौतिक देह भी ज्यादा से ज्यादा जटिल होती जाती है. एक पशु का भौतिक शरीर मानव देह से कम जटिल होता है, क्योंकि मानव मन पशु मन से ज्यादा जटिल हैं. भिन्न-भिन्न मानसिक विषयों से भिन्न-भिन्न मानसिक आभोगों से मन को हटाकर उसे परम सत्ता की ओर मोड़ देना चाहिए. मन की इसी गति की प्रक्रिया को एकाग्रता की प्रक्रिया कहते हैं. एकाग्रता एक बड़ी साधना है, एक बड़ी आध्यात्मिक साधना है. इसके साथ कुछ सहायक साधनाएं भी हैं. आसन और प्राणायाम इसके सहायक तत्व हैं. ये साधना नहीं है, इन्हें 'साधनांग' कहा जाता है. अब मानसिक गति की इस प्रक्रिया में यदि मन भारी हो जाये, तब इसके आगे बढ़ना संभव नहीं हो पायेगा. जागतिक अशुद्धियों से मन को खाली करना और मन को जागतिक अशुद्धियों से कैसे मुक्त किया जाता है? इसके लिए समाज की स्वार्थरहित सेवा करनी है, बिना जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा लिंग के विचार से सेवा करनी है.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

आपके पत्र

दुखद है आतंकी को जी बोलना

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सभा में कंधार मामले का जिक्र करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के सरगना व पुलवामा हमले के जिम्मेदार मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है. कांग्रेस के नेताओं द्वारा आतंकियों को सम्मान देकर संबोधित करने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह आदि नेताओं ने भी आतंकियों को सम्मान देते हुए संबोधित किया है. प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना और एक आतंकी के लिए, जो मानवता का दुश्मन है, जो पुलवामा में हमारे 40 से अधिक जवानों की मौत का जिम्मेदार है, उसके लिए इतना सम्मान आश्चर्यजनक लगता है. उन जवानों के परिवारों ने जो खोया है, उसे तो हम वापस नहीं दे सकते पर ऐसी भाषा का प्रयोग कर उनके बलिदान का मजाक उड़ाना गलत है. इससे जवानों का मनोबल गिरता है. नेताओं को अपनी भाषा और शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए.

कन्हाई, रांची

कश्मीर में विस चुनाव पर रोक

रविवार को जब आम चुनाव की तिथि की घोषणा हुई, तो लगा था कि इसके साथ ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो जायेगी, मगर सिर्फ चार राज्यों के लिए घोषणा हुई. आंध्र, अरुणाचल, सिक्किम और ओडिशा. जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था. आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां सब कुछ ठीक होने और स्थिति नियंत्रण में होने की बात होती है, वहां छह लोकसभा सीटों के चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है, मगर विधानसभा चुनाव के लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं. अनंतनाग की एक सीट को तीन चरणों में करवाया जा रहा है फिर क्यों नहीं ऐसी ही व्यवस्था करके विधानसभा चुनाव भी कराया जा सकता था. अभी चंद महीने पहले ही वहां पंचायत चुनाव करवाये गये हैं. बारामूला को आतंक से मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है. ऐसे में इस तरह के फैसले से तो लग रहा है कि घाटी की हालत निरंतर बदतर होती जा रही है. इस फैसले से विश्व को भी गलत संदेश जायेगा.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

महिला वोट बैंक की राजनीति

बीजद ने ओड़िसा में चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. इसकी जितनी भी सराहना की जाये, कम है. यह नवीन पटनायक का साहसिक कदम है. इससे दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए. चुनाव के समय तो वोट बैंक की राजनीति खूब होती है, पर धरातल पर महिलाओं के लिए बहुत कम आरक्षण है. हम सभी महिला सशक्तिकरण की बातें करते है. जरूरत है कि धर्म के नाम पर वोट बैंक न बनाकर महिला वोट बैंक बनाये. अभी तो कुछ घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि आचार संहिता लागू हो गयी है, पर जिनको करना है, वे घोषणाओं का इंतजार नहीं करते. विभिन्न पार्टियां अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को तैयार करें. महिलाओं को भी चाहिए कि वे अपनी खुद की छवि बिना किसी निर्भरता के गढ़े.

सीमा साही, बोकारो

कुछ अलग

मैं भी वही करूं की प्रतियोगिता!

संतोष उत्सुक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
santoshutsuk@gmail.com

देश की मिली-जुली संस्कृति में गन्ना, रस, गुड़, नींबू, नीम, करेला और शहद सब मिल-जुल कर रहते हैं. कभी मीठा ज्यादा हो जाये, तो कहने लगते हैं कि जीवन में कड़वा भी होना चाहिए, ताकि मीठे के महत्व से वाबस्ता रहें. फीकी चाय पीने की आदत डाल लो, तो सेहत के लिए वही अच्छी लगने लगती है. अस्वस्थता का मजा लेनेवाले सुबह शुगर की गोली खा लेते हैं और दिनभर मीठा चबाते रहते हैं. दूसरों को सुबह उठने के लिए समझाते हैं और खुद देर तक सोये रहते हैं. दूसरा तीसरे को पीट रहा हो, तो पहला और चौथा भी हाथ धो लेता है. पहला पाप सफल हो जाये, तो दूसरा अधिकार जैसा लगने लगता है. लूट अधिकृत हो जाये, तो पाप एक तरह से पुण्य में तब्दील हो जाता है.

बदलते वक्त में एक-दूसरे से प्रेरित हो अनगिनत व्यक्ति, मैं भी, मैं भी करने लगते हैं. जब चाहे बदल दिये जानेवाले इतिहास के अनुसार सफलता, शोहरत और माया ने मिलकर यही गीत तो गाया है. नर और नारी इस समानांतर रास्ते पर निरंतर धंसते जा रहे हैं. भारत में आज शरीर के लिए रोटी से भी अधिक जरूरी चीज हो चुके मनोरंजन को नये सफल रास्तों पर ले जाने के लिए मैं भी, मैं भी की बड़ी होड़ मची हुई है. कुछ नया रचना कितना आसान हो गया है, ढेर सारे रास्ते हैं और आराम से चौबीस घंटे उपलब्ध भी.

आज की प्रतिभा ने पर्यावरण के तीन सिद्धांत रियूज, रिसाइकिल व रिपेयर में रिमिक्स और रिक्रिएट भी मिलाकर मनोरंजन का नया पर्यावरण संभाल लिया है. आदम और हव्वा द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर मां, बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी व दोस्त और असंख्य रूपों में पूजी जानेवाली देवी के प्रतिरूप को कोका कोला से लेकर शराब तक बताते गाने हिट होने के बाद, अन्य आदम और हव्वाओं के बीच, मैं भी, मीटू, मैं भी, करते हुए सफलता हड़पने में देर न लगाने के लिए लालच प्रतियोगिता चल रही है. इस प्रतियोगिता को जीतनेवाली हर टीम में मां, बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी व दोस्त बराबर सक्रिय हैं. वे भी इस सफलता में बराबर की हिस्सेदार हैं. लेकिन, क्या वे केवल पैसा और प्रसिद्धि के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जिम्मेदार नहीं?

पूरी दुनिया में मनोरंजन का जाल बुन चुके पंजाबी के तो हर दूसरे गाने में सस्ते 'मैंभी' उपलब्ध है. असामाजिक सुरक्षा के मौसम में कुड़ी दारू वरगी, नितरी शराब वरगी, निकली शराब वरगी, कबूतर वरगी, ह्विस्की की बोतल वरगी और भी कितने ही वर्गीकरण संभावित हैं. इन गानों में कुड़ियां खुद भी शामिल होकर 'निर्भय मनोरंजन नीति' स्थापित कर रही हैं. कहीं कुड़ियां ही कुड़ियों की यानी खुद अपनी दुश्मन तो नहीं होती जा रही हैं! क्या बेरोजगारी और सांस्कृतिक अकाल से, मनोरंजन समाज में आसानी से जगह दिलाऊ 'मैं भी वही करूं की प्रतियोगिता' चल रही है? सोचना होगा बॉस! समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसलिए हम सभी को ही इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा.

देश दुनिया से

वेनेजुएला संकट और उसका समाधान

इसी वर्ष 23 जनवरी को जब जुआन गुआडो ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था, तब उन्हें लगा था कि सत्ता में बदलाव करना आसान होगा. उधर वाशिंगटन में भी गुआडो और उनके समर्थकों ने मदुरो सरकार और उसके जमीनी समर्थकों को बेहद कमजोर आंका था. लेकिन वेनेजुएला की सेना ने न सिर्फ तुरंत तख्तापलट किया, बल्कि संकट उत्पन्न करने के विपक्ष के प्रयासों को मानने से इंकार कर दिया था. इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कथित तौर पर सैन्य सहायता जुटाने में असफल रहने के लिए गुआदो को फटकार लगायी थी, इससे हताश विपक्षी नेता को स्वतंत्रता के लिए सभी विकल्पों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसे क्षेत्रीय नेताओं ने अवरुद्ध कर दिया था. भले ही अभी गुआदो के तख्ता पलट की कोशिश ध्वस्त हो गयी है, लेकिन वेनेजुएला एक गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ है और तेजी से बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वहां के आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है. जैसे-जैसे सैन्य हस्तक्षेप का खतरा बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक हलकों में संवाद से लेकर नये चुनाव तक सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं.

जॉर्ज सिसेरिएलो महेर

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है